बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १९ फरवरी, १९७५ ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
षष्ठ विहार विधान-सभा के दशम सत्र के अनागत अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—९, १० एवं ११	१-९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—३११ से ३२१, ३२६, ३२७, ३२९, ३३७, ३४२, ३४४ से ३४६, ३५०, ३५१, ३५८, ३५९, ३६२, ३६३, ३६७, ३६८, ३६९, ३७१, ३७३, ३७६, ३८०, एवं ३८१	९-४६
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर —	४७-२९९
दैनिक निबंध :	३०१-३०३

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

सासाराम से सिलौथू सड़क में काम लगाये हुए ३ वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हो सका है, सिर्फ पत्थर गिरा हुआ है, जिसके फलस्वरूप गाड़ियों का आना-जाना बन्द है, यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कब तक तैयार कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग—यह बात सही है कि उक्त सड़क में कार्य तीन वर्षों से हो रहा है। सभी कार्य ३० जून, १९७५ तक पूरा करा देने का प्रयास किया जा रहा है।

नावानगर में बी० डी० ओ० की प्रतिनियुक्ति।

अ०सू०-१४१। **श्री लाल बिहारी प्रसाद**—क्या मंत्री सामुदायिक विकास विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नावानगर प्रखंड में गत ८ माह से बी० डी० ओ० के पद रिक्त है, यदि हां, तो सरकार उक्त प्रखंड में बी० डी० ओ० की प्रतिनियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग—श्री शिवनाथ तिवारी, सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, नावानगर को कार्मिक विभाग के ज्ञापांक ३६५१, दिनांक १२ मार्च, १९७४ द्वारा निलम्बित होने के फलस्वरूप उक्त प्रखंड खाली पड़ गया है। कार्मिक विभाग से पदाधिकारी की सेवायें मांगी गयी है। प्राप्त होते ही नावानगर प्रखंड में एक पदाधिकारी का पदस्थापन तुरत कर दिया जायगा। अभी स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्य चलाया जा रहा है।

जिला पंचायत पर्षद् का गठन।

अ० सू० १२७। **श्री लोकनाथ प्रसाद**—क्या मंत्री, ग्राम पंचायत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य भर में जिन जिन जिलों में जिला पंचायत पर्षद् का गठन नहीं हुआ है, उन जिलों में क्या सरकार १९७५ के जुलाई तक जिला पंचायत पर्षद् का गठन करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग—ऐसे जिलों में जिला पर्षद् गठित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।